

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 13-08-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 13 Aug, 2025

Edition : International Table of Contents

| | |
|--|--|
| Page 01 Syllabus : GS 3 : Indian Economy | खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के कारण खुदरा मुद्रास्फीति 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर पहुँच गई |
| Page 04 Syllabus : GS 2 : International Relations | सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की यात्रा से पहले 10 समझौता ज्ञापनों पर चर्चा |
| Page 06 Syllabus : GS 3 : Science and Technology | कैबिनेट ने चार सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दी |
| Page 10 Syllabus : GS 3 : Science and Technology | सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है? |
| Page 12 Syllabus : GS 3 : Indian Economy | सरकार ₹3.69 लाख करोड़ के उपकरण को निर्धारित कोष में स्थानांतरित करने में विफल रही: CAG |
| Page 09 : Editorial Analysis Syllabus : GS 3 : Indian Economy | रोज़गार सृजन के मिथक का खंडन |

Page 01 : GS 3 : Indian Economy

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से मापी जाने वाली खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में 1.55% पर आ गई, जो जून 2017 के बाद सबसे कम है। यह दर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 2-6% के आरामदायक दायरे से नीचे है और लगातार नौवें महीने गिरावट दर्ज हुई है। प्रमुख कारण खाद्य वस्तुओं में कीमतों की गिरावट है, जिसे अनुकूल कृषि स्थिति और सांख्यिकीय उच्च आधार (High Base) ने सहारा दिया है।

मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण

1. गिरावट के कारण

- खाद्य मूल्य अपस्फीति (Deflation): जुलाई 2025 में खाद्य एवं पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति -0.8% रही, जबकि जुलाई 2024 में यह 5.1% थी।
 - सब्जियाँ: -21%
 - दालें: -14%
- कारण: बेहतर मानसून प्रगति, पर्याप्त जलाशय स्तर, मज़बूत खरीफ बुवाई।

2. कोर मुद्रास्फीति की स्थिति

- कोर मुद्रास्फीति (खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर) 4.4% से घटकर 4.1% पर आ गई, जो RBI के 4% लक्ष्य के करीब है।
- अन्य श्रेणियाँ स्थिर: आवास 3.2%, वस्त्र व जूते-चप्पल 2.5%, पान/तंबाकू 2.4%।

3. वैश्विक संदर्भ

- वैश्विक आर्थिक मंदी से कमोडिटी कीमतें नरम रहीं।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ऊँचे शुल्क (Tariffs) का असर कम मांग से संतुलित हो रहा है।

4. जोखिम एवं सतर्कता बिंदु

- ऊर्जा आपूर्ति जोखिम: अमेरिकी दबाव में रूस से तेल आयात बंद करने की स्थिति में भारत को कुवैत/इराक से आपूर्ति बढ़ानी पड़ सकती है।
- High Base Effect: वर्तमान गिरावट पिछले वर्ष के ऊँचे दामों की तुलना से है; यदि खाद्य या ईंधन में झटका आया तो रुझान पलट सकता है।

5.

Retail inflation hits 8-year low of 1.55% as food prices drop



SOURCE: MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Retail inflation in India slipped to 1.55% in July, its lowest rate since June 2017, driven by a drop in food prices. This is below the Reserve Bank of India's comfort band of 2% to 6%. The Consumer Price Index (CPI), released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation on Tuesday, showed that inflation has been easing for nine consecutive months.

The rate of inflation in the food and beverages category came in at -0.8% in July, lower than the -0.2% seen in June, and the 5.1% rate in July 2024.

"In the food basket, there was deflation in key items such as vegetables, pulses, spices, and meat," said Rajani Sinha, chief economist at CareEdge Ratings. "Looking ahead, food inflation is likely to remain contained." Vegetable and pulses inflation contracted 21% and 14% respectively, driven by a high base and falling prices. Ms. Sinha said the good progress of the monsoon, adequate reservoir levels, and strong *khari* sowing bode well for agricultural output and food price stability.

Core inflation, which excludes the impact of food and fuel prices, also eased to 4.1% in July 2025 from 4.4% in the previous month, nearly at the RBI's

target of 4%.

The other broad categories in the CPI saw little change from the previous month. The paan, tobacco, and intoxicants category saw inflation remain flat at 2.4% in July. Similarly, the clothing and footwear category saw inflation ease marginally to 2.5% in July from 2.5% in June.

Inflation in the housing segment remained at 3.2% in July, while the fuel and light category saw inflation quicken to 2.7% in July from 2.5% in June.

High base benefit

Dipanwita Mazumdar, an economist at the Bank of Baroda, said that a statistical high base will continue to keep the inflation rate down between September and December 2025.

"The current cycle is acting in favour of us when the inflationary impact from tariffs is the centre point of global discussions," she said in a note. "We expect the downside risk to global growth will largely keep international commodity prices in check. This is expected to partly negate the higher tariff rates in place." However, she added that India needs to be watchful in case it has to completely stop buying Russian oil in compliance with U.S. President Donald Trump's demands. "In this case, some diversification towards Kuwait and Iraq would also lend support."

6. नीतिगत निहितार्थ

- कम मुद्रास्फीति से RBI को मौद्रिक नीति में नरमी बनाए रखने की गुंजाइश।
- ग्रामीण मांग व घरेलू खपत को सहारा।
- लेकिन आपूर्ति झटकों (तेल, जलवायु प्रभाव) के प्रति सतर्कता आवश्यक।

निष्कर्ष

खुदरा मुद्रास्फीति में यह तेज गिरावट घरेलू कृषि की अनुकूल स्थिति और वैश्विक कमोडिटी बाज़ार में नरमी का परिणाम है। यह अल्पकालिक मूल्य स्थिरता और RBI के लिए नीति लचीलापन दर्शाता है, किंतु इसकी स्थिरता के लिए ऊर्जा आपूर्ति, जलवायु जोखिम और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान देना होगा। UPSC दृष्टिकोण से यह उदाहरण मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीति, कृषि और वैश्विक व्यापार के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. जुलाई 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर 2% से कम रही।
2. कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन की कीमतें शामिल होती हैं।
3. RBI का मुद्रास्फीति के लिए आरामदायक दायरा 2-6% है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Ans: b)

UPSC Mains Practice Question

Ques: खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट का भारत की मौद्रिक नीति, ग्रामीण मांग और समग्र आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? विवेचना कीजिए। (150 Words)

भारत और सिंगापुर के बीच 2015 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) ऐतिहासिक संबंधों, आर्थिक पारस्परिकता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान सुरक्षा हितों पर आधारित है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की आगामी भारत यात्रा से पहले, दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में लगभग 10 प्रमुख समझौता ज्ञापन (MoUs) पर वार्ता चल रही है। इन पर चर्चा तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्रीस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR) में होने की संभावना है।

10 MoUs under discussion ahead of Singaporean PM Lawrence Wong's visit

Kallol Bhattacharjee
NEW DELHI

Around 10 major MoUs are under discussion between India and Singapore as the two sides are preparing for the proposed India visit of Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, diplomatic sources have said. The visit of Mr. Wong and the agreements to be sealed during the visit are expected to feature in the third India-Singapore Ministerial Roundtable (ISMR) that will be held here on Wednesday.

External Affairs Minister S. Jaishankar, Finance Minister Nirmala Sitharaman, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of Information Technology Ashwini Vaishnaw are among those who will participate in the ISMR.



PM Narendra Modi with his Singaporean counterpart Lawrence Wong at a meeting in Singapore in September 2024. FILE PHOTO

The Singaporean side will be represented by Gan Kim Yong, Deputy Prime Minister and Minister for Trade and Industry; K. Shanmugam, Coordinating Minister for National Security and Minister for Home Affairs; Vivian Balakrishnan, Minister for Foreign Affairs; Josephine

Teo, Minister for Digital Development and Information; Tan See Leng, Minister for Manpower, and Jeffrey Siow, Acting Minister for Transport. A diplomatic source said that the Ministers are expected to focus on digital technology, connectivity, healthcare and sustainability.

मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण

1. उच्च स्तरीय भागीदारी

- भारत: विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव।
- सिंगापुर: उप प्रधानमंत्री एवं व्यापार मंत्री गन किम योंग, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, डिजिटल विकास मंत्री, श्रम मंत्री और परिवहन मंत्री।

2. संभावित एमओयू के क्षेत्र

- डिजिटल तकनीक व साइबर सुरक्षा: फिनटेक, एआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर गवर्नेंस में सहयोग।

- कनेक्टिविटी: वायु, समुद्री और डिजिटल कनेक्टिविटी, आसियान आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ाव।
- स्वास्थ्य सेवा: सार्वजनिक स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, चिकित्सकीय अनुसंधान और महामारी तैयारी।
- सतत विकास: स्वच्छ ऊर्जा, शहरी नियोजन, ग्रीन फाइनेंस और जलवायु अनुकूलन उपाय।

3. भारत के लिए रणनीतिक महत्व

- आर्थिक प्रवेशद्वार: सिंगापुर, आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार व निवेश साझेदार और एफडीआई का प्रमुख स्रोत।
- हिंद-प्रशांत सहयोग: आसियान आउटलुक ऑन इंडो-पैसिफिक और भारत की एक्ट ईस्ट नीति में सामंजस्य।
- वित्तीय केंद्र का लाभ: सिंगापुर की उन्नत वित्तीय सेवाओं के माध्यम से वैश्विक पूंजी तक भारत की पहुँच।

4. भूराजनीतिक संदर्भ

- यह यात्रा आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरचना, अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और हिंद-प्रशांत में लचीले नेटवर्क निर्माण की पृष्ठभूमि में हो रही है।
- दोनों देशों के लिए दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य की समुद्री सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

5. चुनौतियाँ एवं सावधानियाँ

- सिंगापुर निवेश के प्रति खुलापन बनाए रखते हुए घरेलू उद्योग की सुरक्षा।
- डिजिटल सहयोग में डेटा सुरक्षा और साइबर मानकों का पालन।
- वैश्विक आर्थिक मंदी से निवेश और व्यापार विस्तार पर प्रभाव।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की यह यात्रा भारत-सिंगापुर संबंधों को रणनीतिक से रूपांतरकारी स्तर पर ले जाने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और सतत विकास लक्ष्यों का समन्वय हो सकता है। प्रस्तावित एमओयू भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती देंगे, आसियान एकीकरण को गहरा करेंगे और हिंद-प्रशांत के उभरते आर्थिक-सुरक्षा ढाँचे में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। दीर्घकालिक सफलता के लिए इन समझौतों का प्रभावी क्रियान्वयन, राष्ट्रीय हितों का संतुलन और वैश्विक अस्थिरताओं के प्रति लचीलापन आवश्यक होगा।

UPSC Mains Practice Question

Ques: भारत-सिंगापुर संबंधों में हाल के उच्च-स्तरीय संवाद और संभावित समझौता ज्ञापन (MoUs) किन-किन क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की क्षमता रखते हैं? इनके भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' और हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए महत्व का मूल्यांकन कीजिए। (150 Words)

तकनीकी आत्मनिर्भरता और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने ₹76,000 करोड़ के 'भारत सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) के तहत चार नए सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में फैले ये संयंत्र ₹4,594 करोड़ के होंगे और भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भागीदारी को मजबूत करेंगे।

Cabinet gives approval for four semiconductor plants

The projects, which will come up in Odisha, Punjab and Andhra Pradesh, will have a cumulative value of ₹4,594 crore, and are being supported by the ₹76,000-crore India Semiconductor Mission

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Union Cabinet on Tuesday approved four projects under the India Semiconductor Mission (ISM). Two of the projects will be in Bhubaneswar in Odisha, and one each will be in Punjab and Andhra Pradesh.

The cumulative value of the projects is ₹4,594 crore. This brings the number of projects under the ₹76,000-crore mission, which provides financial support to semiconductor units, to 10.

The first chip from one of the previous six units – some are competing, so it's not clear which – is expected to be rolled out by the end of the year.

The firms behind the four new projects are SiC-Sem (which will make a silicon carbide integrated fa-

Semiconductor unit in Odisha – SiCSem

- Applicant: **SiCSem Pvt Ltd**
- Investment: **Rs 2,066 Cr**
- Capacity:
 - Silicon Carbide based diodes and MOSFETs
 - SiC based fab: 60 thousand wafers per year
 - ATMP capacity: 96 million units per year

Bhubaneswar, Odisha

Chips will be used in

Evolving field: Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw announces the Cabinet decisions in New Delhi on Tuesday. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

cility in Info Valley, Bhubaneswar); Continental Device India Private Limited, which will expand its existing “discrete semiconductor manufacturing facility” in Mohali; 3D Glass Solutions Inc., which will set up a “vertically integrated advanced packaging and embedded glass

substrate unit” in Bhubaneswar; and Advanced System in Package (ASIP) Technologies, which will set up a semiconductor unit in Andhra Pradesh, with the location yet to be chosen.

Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaish-

naw said that having the capacity to work on silicon carbide technology, an “evolving” field, was strategically important for India. “IIT Bhubaneswar already has a ₹45 crore investment in a silicon carbide research unit, and the results have been very good,” he added.

निर्णय के मुख्य बिंदु

1. परियोजनाएं और स्थान

- **ओडिशा (भुवनेश्वर):**
 - SiCSem: सिलिकॉन कार्बाइड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी (इन्फो वैली)।
 - 3D Glass Solutions Inc.: एडवांस्ड पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सब्सट्रेट यूनिट।
- **पंजाब (मोहाली):**
 - Continental Device India Pvt. Ltd.: डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग यूनिट का विस्तार।
- **आंध्र प्रदेश:**
 - Advanced System in Package (ASIP) Technologies: सेमीकंडक्टर यूनिट (स्थान तय होना बाकी)।

2. रणनीतिक महत्व

- सिलिकॉन कार्बाइड तकनीक: पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए अहम।
- अनुसंधान सहयोग: IIT भुवनेश्वर का ₹45 करोड़ का सिलिकॉन कार्बाइड रिसर्च यूनिट औद्योगिक उपयोग में योगदान देगा।
- भौगोलिक विविधता: पारंपरिक टेक हब से बाहर विनिर्माण केंद्रों का विकास।

3. भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) संदर्भ

- 2021 में लॉन्च, लक्ष्य: भारत को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैनुफैक्चरिंग और पैकेजिंग का वैश्विक केंद्र बनाना।
- फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूनिट, और असेंबली/टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।
- मंजूर परियोजनाओं की कुल संख्या अब 10 हो गई है, और पहले चिप के इस वर्ष के अंत तक तैयार होने की संभावना है।

4. आर्थिक और सामरिक लाभ

- आर्थिक गुणक प्रभाव: इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, रोज़गार और निर्यात को बढ़ावा।
- सप्लाय चेन सुरक्षा: पूर्वी एशियाई सप्लाय चेन पर निर्भरता कम होगी।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: रक्षा, दूरसंचार और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वदेशी चिप क्षमता आवश्यक।

5. चुनौतियाँ

- पूंजी और तकनीकी निवेश: सेमीकंडक्टर फैब के लिए बड़े निवेश और तकनीकी हस्तांतरण की आवश्यकता।
- कुशल मानव संसाधन: चिप डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और पैकेजिंग में विशेषज्ञता का विकास जरूरी।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा: ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा।

निष्कर्ष

चार नए सेमीकंडक्टर संयंत्रों की मंजूरी भारत की टेक्नोलॉजिकल संप्रभुता और वैश्विक चिप इकोसिस्टम में सहभागिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ₹76,000 करोड़ का ISM वित्तीय आधार प्रदान करता है, लेकिन सफलता समयबद्ध क्रियान्वयन, उद्योग-शैक्षणिक सहयोग और रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी पर निर्भर करेगी। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लक्ष्य को साकार करने के लिए अनुसंधान से लेकर बड़े पैमाने पर विनिर्माण तक एंड-टू-एंड सेमीकंडक्टर क्षमता विकसित करनी होगी।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: हाल ही में समाचारों में उल्लेखित सिलिकॉन कार्बाइड तकनीक का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है?

- (a) नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ
- (b) वस्त्र निर्माण
- (c) मत्स्य पालन
- (d) पर्यटन अवसंरचना

Ans: (a)

UPSC Mains Practice Question

Ques: भारत में सिलिकॉन कार्बाइड तकनीक के विकास के सामरिक एवं आर्थिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। (150 Words)

आज के डिजिटल युग में इंटरनेट पहुंच आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। पारंपरिक भू-आधारित इंटरनेट नेटवर्क, विशेषकर कम आबादी वाले और दूरस्थ क्षेत्रों में, आर्थिक व भौगोलिक सीमाओं के कारण सीमित हैं। भारत में जल्द ही स्टारलिनक की शुरुआत, लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रह समूहों के माध्यम से उच्च गति, कम विलंबता (low latency) वाला इंटरनेट, देश के सबसे दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँचाने में एक क्रांतिकारी कदम होगी।

भू-आधारित नेटवर्क की सीमाएँ

- उच्च अवसंरचना लागत – केबल बिछाना और टावर बनाना कम घनत्व वाले क्षेत्रों में आर्थिक रूप से अव्यावहारिक।
- आपदाओं के प्रति संवेदनशील – बाढ़, भूकंप, भूस्खलन से सेवाएं बाधित।
- सीमित गतिशीलता – जहाज़, विमान या चलती गाड़ियों जैसी मोबाइल प्लेटफॉर्म को सेवा देने में कमी।
- धीमी तैनाती – भौतिक अवसंरचना बनाने में अधिक समय।

उपग्रह इंटरनेट का द्वैत स्वरूप (Dual Use Nature)

- नागरिक उपयोग – दूरस्थ शिक्षा, टेलीमेडिसिन, आपदा प्रबंधन, स्मार्ट कृषि, लॉजिस्टिक्स, पर्यावरण निगरानी।
- सैन्य उपयोग – दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षित संचार, ड्रोन संचालन, युद्धक्षेत्र में सैनिकों का समन्वय (जैसे यूक्रेन युद्ध, सियाचिन में भारतीय सेना)।
- सुरक्षा चुनौतियाँ – आतंकवादी व आपराधिक नेटवर्क द्वारा दुरुपयोग की संभावना; नियंत्रण व विनियमन आवश्यक।

उपग्रह इंटरनेट कैसे काम करता है?

- स्पेस सेगमेंट – संचार उपकरणों वाले उपग्रह।
- ग्राउंड सेगमेंट – उपयोगकर्ता टर्मिनल, गेटवे स्टेशन, नियंत्रण केंद्र।
- सिग्नल प्रवाह – उपयोगकर्ता टर्मिनल से डेटा → उपग्रह → धरती या अन्य उपग्रह तक ऑप्टिकल लिंक्स द्वारा।

Why are ground-based internet networks economically unviable? How does the dual nature of satellite internet manifest? What are the three main orbits in which such satellites are deployed? Will it be more expensive than terrestrial broadband?

EXPLAINER

Ashwin Prasad

In today's increasingly digitised world, internet connectivity is an absolute necessity, across both military and civilian domains. With Elon Musk's Starlink about to make its debut very soon in India, internet infrastructure is going to fundamentally change.

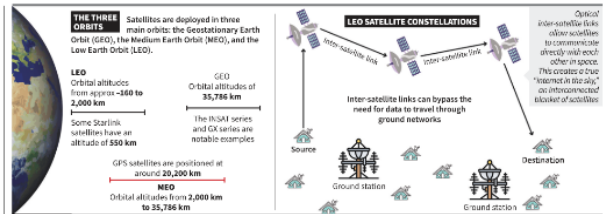
Why do we need satellite internet? Ground-based networks use cables and towers. They are the most common form of internet provision, especially in densely populated urban areas. However, they have some limitations. Their reliance on physical infrastructure makes them economically unviable in sparsely populated regions. They are also vulnerable to disruptions from natural disasters such as floods and earthquakes. Furthermore, they often cannot meet the demand for on-the-go connectivity in remote locations or for temporary operations.

Satellite internet emerges as a powerful solution to these challenges. Functioning on a global scale, it provides extensive and resilient coverage. This coverage functions regardless of terrain or the presence of terrestrial infrastructure. It can be deployed rapidly to manage sudden demand surges, and also provides connectivity within moving platforms like airplanes and remote sites such as offshore oil rigs. Thus, satellite internet is not merely a backup system. It is a transformative technology with the potential to reshape the digital economy, civil infrastructure, and military strategy.

What are the features of satellite internet?

The advent of satellite mega-constellations such as Starlink signals a new era in space-based internet. These comprise hundreds or even thousands of satellites orbiting a few hundred kilometres above Earth. This "internet in the sky" offers a plethora of applications in military operations, disaster response, healthcare, agriculture, and transportation. However, this technology has a dual-use nature, serving both civil and military ends. This introduces complex security dynamics. Contemporary events underscore this technology's profound impact. When Hurricane Harvey struck the Texas coast in 2017, it knocked out 70% of cell towers in affected regions. Viasat's satellite internet became a lifeline for coordinating rescue operations. Similarly, in the Russia-Ukraine war, SpaceX's Starlink has been pivotal for Ukrainian defence forces. They have relied on it for coordinating troop movements, medical evacuations, and drone operations. Ukrainians even fitted Starlink devices on drones to bypass Russian jamming systems. Satellite internet also enhances operational readiness in isolated conflict zones, as shown by the Indian Army's use of it on the Siachen Glacier. Conversely, its borderless nature facilitates illicit use. Security forces in India have confiscated smuggled Starlink devices from insurgent groups and drug racketeers. These instances reveal that control over satellite internet infrastructure is becoming a new dimension of national power.

How does satellite internet work? A satellite internet network is composed of a space segment and a ground segment. The space segment consists of the satellites in orbit, while the ground



segment includes all equipment on Earth that communicates with them. The satellites are the most capital-intensive component. They carry communication payloads for data transmission and have a service life of five to 20 years. Their deployment requires careful planning, especially concerning orbital altitude, which determines the satellite's capabilities and coverage. Satellites are deployed in three main orbits: the Geostationary Earth Orbit (GEO), the Medium Earth Orbit (MEO), and the Low Earth Orbit (LEO).

What are differences between satellites deployed in different orbits?

GEO satellites orbit at 35,786 km above the equator. They match the Earth's rotation, allowing them to remain stationary relative to a point on the ground. This high altitude allows a single GEO satellite to cover nearly one-third of the Earth's surface, though not the polar regions. Viasat's Global Xpress (GX) system is a notable example. GEO satellites are also typically large. They act as "beamed pipes," simply relaying signals back to Earth without processing them. Their significant drawback is high propagation latency. The long distance signals must travel result in delays, making GEO systems unsuitable for time-sensitive applications like video conferencing or real-time transactions. MEO satellites operate at altitudes between 2,000 km and 35,786 km. They offer a compromise between GEO and LEO systems. Their latency is lower than that of GEO satellites, but they still require a constellation for global coverage. The OSO MEO constellation, for instance, consists of 20 satellites. However, their latency is often insufficient for many real-time applications, and the satellites remain large and costly to launch. LEO satellites orbit at altitudes below 2,000 km. Their proximity to Earth results in very low latency. They are also smaller, often table-sized, making them



And conflict: Servicemen of the Armed Forces of Ukraine set up a Starlink satellite internet system, amid Russia's attack on Ukraine, near Pokrovsk in the Donetsk region, Ukraine on April 10, 2023.

cheaper and quicker to deploy. Their main disadvantage is their smaller coverage area. A single Starlink LEO satellite's footprint is comparable to an Indian metropolitan city. To achieve global coverage, LEO systems form "mega-constellations". These are networks of hundreds or thousands of satellites working in unison. Starlink has over 7,000 satellites in orbit, with plans for up to 42,000.

How do mega-constellations work?

LEO mega-constellations leverage their numbers to turn limitations into strengths. The smaller satellites are capable of on-board signal processing. This enhances data transmission efficiency, improves signal quality, and allows for greater flexibility. This on-board intelligence simplifies the user terminals on the ground. Terminals become smaller, cheaper, and more accessible to individual households.

A key innovation was the use of optical inter-satellite links. These allow satellites to communicate directly with each other in space. This creates a true "internet in the sky," an interconnected blanket of satellites. This network can route data globally with minimal reliance on ground stations, reducing latency and increasing efficiency. However, maintaining continuous connectivity is a challenge. LEO satellites move at nearly 27,000 km per hour. They stay within a user's line of sight for only a few minutes. To ensure uninterrupted service, the network must seamlessly "hand off" the connection from one satellite to the next. This is achieved with steerable antennas that can track multiple users and ground stations simultaneously, much like moving spotlights on a stage.

What are the applications of satellite internet?

For the end user, modern LEO satellite internet is a major advancement. User terminals are now compact and easy to

Nations now recognise satellite internet as a new dimension of power.

It is imperative for countries like India to develop comprehensive strategies to integrate the technology into national resilience plans. India should also leverage it to bridge the digital divide and foster economic development.

set up without professional help. However, the service is still more expensive than terrestrial broadband. While terminals cost around \$500, the cost is often justified for those in remote areas or in industries where connectivity is paramount.

The future promises even greater accessibility. Companies like AST SpaceMobile and Starlink are testing direct-to-smartphone services. This innovation could eliminate the need for separate user terminals altogether. As the technology becomes mainstream, specialised hardware may be integrated directly into devices like smartphones and laptops.

The applications for satellite internet are vast and transformative. In communications, it provides network access to remote areas and enables the Internet of Everything (IoE). In transportation, it will enhance navigation systems, support self-driving cars, and improve logistics. In public administration and disaster management, it can power smart cities, provide early warnings, and coordinate rescue efforts. The healthcare sector can benefit from telemedicine and remote patient monitoring. Agriculture can leverage it for precision farming and crop health analysis. It also has significant applications in environmental monitoring, energy exploration, tourism, and defence.

Therefore, satellite internet presents immense opportunities but also creates complex security and regulatory challenges. Nations now recognise satellite internet as a new dimension of power.

It is imperative for countries like India to develop comprehensive strategies to integrate the technology into national resilience plans. India should also leverage it to bridge the digital divide and foster economic development. Finally, active participation in shaping its international governance is crucial as these mega-constellations will define the next era of global connectivity and strategic advantage.

Ashwin Prasad is with the

Takshashila Institution.

THE GIST

Ground-based networks use cables and towers. However, they have some limitations. Their reliance on physical infrastructure makes them economically unviable in sparsely populated regions.

When Hurricane Harvey struck the Texas coast in 2017, it knocked out 70% of cell towers in affected regions. Viasat's satellite internet became a lifeline for coordinating rescue operations.

For the end-user, modern LEO satellite internet is a major advancement. User terminals are now compact and easy to set up without professional help. However, the service is still more expensive than terrestrial broadband.

उपग्रहों की तीन प्रमुख कक्षाएँ (Orbits)

| कक्षा | ऊँचाई | विशेषताएँ | उदाहरण | सीमाएँ |
|-------|-------------------|--|-----------|---|
| GEO | ~35,786 किमी | पृथ्वी के साथ स्थिर, 1/3 सतह कवरेज | Viasat GX | उच्च विलंबता (~600ms), रीयल-टाइम कार्य के लिए अनुपयुक्त |
| MEO | 2,000–35,786 किमी | GEO से कम विलंबता, LEO से कम उपग्रह आवश्यक | O3b | कुछ रीयल-टाइम सेवाओं के लिए पर्याप्त नहीं |
| LEO | <2,000 किमी | बहुत कम विलंबता (<50ms), छोटे व सस्ते उपग्रह | Starlink | वैश्विक कवरेज हेतु हजारों उपग्रहों की आवश्यकता |

मेगा-नक्षत्र (Mega-Constellations) व प्रमुख नवाचार

- हजारों LEO उपग्रह मिलकर कम विलंबता वाला वैश्विक नेटवर्क बनाते हैं।
- ऑन-बोर्ड प्रोसेसिंग – डेटा गुणवत्ता व दक्षता में सुधार।
- ऑप्टिकल इंटर-उपग्रह लिंक – धरती पर बार-बार डेटा रूट करने की आवश्यकता कम।
- सीमलेस हैंडऑफ़ – उपग्रहों की तेज़ गति (~27,000 किमी/घंटा) के बावजूद निरंतर कनेक्शन।

आर्थिक पहलू

- लागत – स्टारलिनक टर्मिनल: ~\$500, मासिक शुल्क: ~\$50।
- स्थलीय ब्रॉडबैंड से महंगा लेकिन दूरदराज़ क्षेत्रों और विशेष उद्योगों में उचित।
- भविष्य की दिशा – सीधे स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी, जिससे अलग टर्मिनल की आवश्यकता खत्म हो सकती है।

मुख्य उपयोग क्षेत्र

- नागरिक क्षेत्र – टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, सटीक कृषि, स्मार्ट सिटी।
- आपदा प्रबंधन – स्थलीय नेटवर्क फेल होने पर संचार बहाल करना।
- परिवहन व लॉजिस्टिक्स – नेविगेशन, स्वचालित वाहन संचालन।
- रक्षा – कठिन भूभाग में सुरक्षित संचार।

चुनौतियाँ व चिंताएँ

- अंतरिक्ष मलबा व टकराव का खतरा।
- स्पेक्ट्रम आवंटन व वैश्विक नियमन।
- साइबर सुरक्षा जोखिम।
- विदेशी प्रदाताओं पर निर्भरता यदि स्वदेशी क्षमता विकसित न हो।

निष्कर्ष

LEO मेगा-नक्षत्र आधारित उपग्रह इंटरनेट, विशेषकर स्टारलिनक जैसी परियोजनाएँ, डिजिटल खाई पाटने और राष्ट्रीय लचीलापन (resilience) बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत के लिए यह तकनीक अपार सामाजिक-आर्थिक अवसर प्रदान करती है, लेकिन साथ ही सुरक्षा, नियमन और रणनीतिक स्वायत्तता की नई चुनौतियाँ भी लाती है। इसलिए, भारत को एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनानी होगी जिसमें अवसंरचना विकास, स्वदेशी क्षमता निर्माण, नियामकीय ढाँचा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी जाए, ताकि लाभ को अधिकतम और जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: निम्नलिखित में से कौन-सा/से लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रह इंटरनेट प्रणाली के लाभ हैं?

1. कम विलंबता (Low latency)
2. वैश्विक कवरेज के लिए कम संख्या में उपग्रहों की आवश्यकता
3. छोटे आकार और कम लागत वाले उपग्रह
4. केवल सैन्य उपयोग के लिए उपयुक्त

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) केवल 1 और 4

Ans: (a)

UPSC Mains Practice Question

Ques: भारत में उपग्रह इंटरनेट प्रौद्योगिकी के संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। क्या यह तकनीक डिजिटल खाई को पाटने में प्रभावी होगी? (150 Words)

सेस ऐसे विशेष प्रयोजन कर होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार किसी विशिष्ट कार्यक्रम या क्षेत्र, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या बुनियादी ढाँचे, के लिए वसूलती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 तक केंद्र ने ₹3.69 लाख करोड़ का सेस उन निधियों में स्थानांतरित नहीं किया जिनके लिए यह वसूला गया था। यह वित्तीय पारदर्शिता, वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और करदाताओं के विश्वास पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

CAG रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

1. **कुल कमी** – ₹3.69 लाख करोड़ का सेस निर्धारित निधियों में नहीं पहुँचा।
2. **मुख्य कमी वाले क्षेत्र** –
 - **तेल उद्योग विकास सेस** –
 - 1974 के तेल उद्योग (विकास) अधिनियम के तहत लगाया गया।
 - 1974-2024 के बीच कुल वसूली: ₹2,94,850.56 करोड़।
 - केवल ₹902.40 करोड़ (1991-92 तक) स्थानांतरित, उसके बाद कोई राशि स्थानांतरित नहीं।
 - **स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस** –
 - 2004 में शिक्षा सेस (2%), 2007 में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सेस (1%), और 2018 में दोनों को मिलाकर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस।
 - 2018-19 से 2023-24 के बीच ₹37,537 करोड़ स्थानांतरित नहीं किया गया।
 - **निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष** – ₹2,505.5 करोड़ की कमी।
 - **राष्ट्रीय राजमार्गों के मौद्रीकरण कोष** – ₹5,968.1 करोड़ की कमी।
3. **आँकड़ों में विसंगति** –
 - वित्त मंत्रालय का दावा: 2018-19 से 2023-24 के बीच ₹3.66 लाख करोड़ स्थानांतरित, जो वसूली से अधिक है।
 - CAG के अनुसार: केवल ₹2.65 लाख करोड़ स्थानांतरित — जिसे सुलझाना आवश्यक।

समस्याएँ और प्रभाव

- **कानूनी उल्लंघन** – अधिनियम के तहत बने कोष में तय उपयोग के लिए राशि नहीं भेजना विधायी मंशा के विपरीत।
- **वित्तीय पारदर्शिता में कमी** – बजट प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित।
- **क्षेत्रीय उद्देश्यों पर असर** – तेल उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे की योजनाओं में संसाधनों की कमी।

Govt. fails to transfer ₹3.69 lakh-cr. cess to designated funds: CAG

The bulk of the short allocations date back to 1974 but others are more recent, the data from the Comptroller and Auditor General shows

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

As of 2023-24, the Centre had failed to transfer ₹3.69 lakh crore worth cess collections to the relevant funds for which they were levied, the Comptroller and Auditor General (CAG) found.

In its report tabled in Parliament, the CAG found shortfalls in transfers to funds created for investor education and protection, monetisation of national highways, development of oil industry and health and education in the country.

Gas/oil cess

The single-largest source of this shortfall in transfers was to do with the Oil Industry Development Board (OIDB). The Oil Industry (Development) Act, 1974 had provided for the setting up of the OIDB for the development of the oil industry. For that purpose, a cess was imposed on crude oil and natural gas.

"We found since FY1974-75 to FY2023-24, total cess on crude oil collected by the Government was ₹2,94,850.56 crore (including ₹18,845.98 crore during FY 2023-24," the CAG said, and "since FY 1974-75 to FY 1991-92, only ₹902.40 crore has been transferred to the OIDB and thereafter no funds have been



Money matters: The single-largest source of shortfall in transfers was to do with the Oil Industry Development Board (OIDB).

transferred."

An analysis by *The Hindu* of the government's budget documents showed it transferred ₹17,730 crore in 2024-25 and budgeted a transfer of ₹19,376 crore in 2025-26 to the fund.

The other large cess collected but not adequately transferred to the relevant fund was the Health and Education Cess. The Government had imposed an Education Cess at 2% with effect from April 1, 2004.

Health & education cess

In 2007, the Government levied an additional Secondary and Higher Education cess of 1% on income tax and surcharge. From April 1, 2018, the levies were replaced with a single 4% Health and Education Cess. The CAG found the Centre did not transfer a

total of ₹37,537 crore collected as cess from 2018-19 to 2023-24 to the education and health funds.

In its reply, the Finance Ministry said between 2018-19 and 2023-24, it transferred ₹3.66 lakh crore to the designated funds, which was in excess of what it had collected from the relevant levies during that time.

Need to reconcile

However, the CAG pointed out Government accounts showed transfer to the funds at ₹2.65 lakh crore.

"This needs to be reconciled by the Ministry," it added. Other funds where there was shortfall were Investor Education and Protection Fund (₹2,505.5 crore) and Monetisation of National Highways Fund (₹5,968.1 crore).

- **संसदीय निगरानी में कमी** – निधियों की निगरानी और रिपोर्टिंग में ढिलाई।
- **जनविश्वास में गिरावट** – earmarked कर के दुरुपयोग से करदाताओं में असंतोष।

संभावित कारण

- **सामान्य राजस्व में मिलाना** – Consolidated Fund of India में राशि रखकर विशेष उपयोग के लिए अलग न करना।
- **राजकोषीय दबाव** – अन्य खर्च पूरे करने के लिए सेस राशि का प्रयोग।
- **प्रशासनिक लापरवाही** – मंत्रालयों के बीच ट्रेकिंग और रिपोर्टिंग में कमी।

आगे की राह

1. **कानूनी प्रावधान सख्त करना** – समयसीमा में निधि हस्तांतरण न करने पर स्पष्ट दंड प्रावधान।
2. **पारदर्शी लेखांकन** – सेस वसूली और हस्तांतरण के लिए अलग सार्वजनिक रजिस्टर।
3. **CAG की नियमित ऑडिट** – earmarked निधियों की वार्षिक समीक्षा।
4. **ऑकड़ों का सामंजस्य** – वित्त मंत्रालय और CAG में डेटा मेल करना।
5. **संसदीय समीक्षा को मजबूत करना** – स्थायी समितियों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की जांच।

निष्कर्ष

CAG की यह रिपोर्ट भारत के सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में एक गंभीर खामी को उजागर करती है— earmarked कर और निधि के बीच असंगति। सेस को एक भरोसेमंद वित्तीय उपकरण बनाए रखने के लिए सरकार को वैधानिक अनुपालन, पारदर्शी रिपोर्टिंग और समय पर निधि हस्तांतरण सुनिश्चित करना होगा। यह केवल कानूनी बाध्यता ही नहीं बल्कि जनता के विश्वास और विकासात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी आवश्यक है।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: भारत में "Oil Industry Development Board (OIDB)" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. OI DB का गठन तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था।
2. इसका उद्देश्य देश में तेल उद्योग के विकास के लिए कार्य करना है।
3. 1991-92 के बाद से इस कोष में नियमित रूप से सेस स्थानांतरित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Ans: (a)

UPSC Mains Practice Question

Ques: भारत में सेस और अधिभार राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते जा रहे हैं, परन्तु निर्धारित निधियों में इनके स्थानांतरण में कमी वित्तीय पारदर्शिता और सुशासन के लिए चुनौती है। हालिया CAG रिपोर्ट के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 Words)

Page : 09 Editorial Analysis

Debunking the myth of job creation

On July 1, 2025, the government approved the Employment Linked Incentive (ELI) Scheme to support employment generation, with an outlay of ₹99,446 crore. However, this raises serious concerns about the target population in a labour market where capital-labour asymmetries, the formal-informal sector divide, and the persistent mismatch between employment opportunities and employability continue to marginalise large sections of the workforce, particularly low-skilled and the informal workers.

Problems with the scheme

While being an ambitious attempt to generate employment, the ELI reflects an employer-centric approach to the labour market. By providing fiscal incentives to employers for creating employment, particularly in the manufacturing sector, the scheme overlooks the persistent mismatch between employability and actual employment opportunities. Incentivising employment generation seems to mimic subsidising capital which may consequently promote existing capital-labour asymmetries. In effect, this may further lead to the strengthening of the bargaining power of employers rather than of the workers, which may enhance the already high wage gaps. This would prove detrimental for workers, especially from the informal and low-skilled segments, who remain excluded from the benefits of the scheme.

At the heart of India's labour market crisis lies not just a lack of jobs but a severe skill mismatch. The Economic Survey 2024-25 reveals that only 8.25% of graduates are employed in roles matching their qualifications. Worse, over 53% of graduates and 36% of postgraduates are underemployed in semi-skilled or elementary occupations. This dismal alignment is further reflected in wage outcomes: only 4.2% of graduates in specialised



Aurolipsa Das

Assistant Professor in the Department of Economics, SRM-University-AP



Ubaid Mushtaq

Assistant Professor in the Department of Economics, SRM-University-AP

Although the ELI Scheme is an attempt to address India's unemployment crisis, the design of the policy could deepen structural inequalities in the labour market

roles earn between ₹4 lakh-8 lakh per annum, while nearly 46% in low-skill jobs earn less than ₹1 lakh. These figures expose not just the inefficiency of India's education-to-employment pipeline, but also the futility of employer-centric incentives in a labour market where workers lack the skills that industry demands. Only 4.9% of Indian youth (15-29 years) have received formal vocational training. In the absence of a robust skilling infrastructure, the ELI Scheme does little more than pay employers to absorb an unprepared workforce.

The scheme tends to prioritise sectors/firms that are already integrated into the formal economy, i.e., those who have already registered with the Employee's Provident Fund Organisation. While this design may seem administratively sound, it indirectly marginalises 90% of the labour force employed in the informal sector, who are already devoid of social security, formal contracts, and stable employment protection. In doing so, it risks establishing structural inequalities rather than resolving them. This restriction and consequent exclusion may exacerbate existing dual labour market structures, where the formal sector is provided with state support and incentives, while the informal sector remains unrecognised in policy initiatives. Such a scheme may also be indirectly reinforcing inequality by channelising fiscal allocation (in other words, public resources) towards the relatively well-off enterprises, leaving behind low-wage, unregistered workers. The state's substantial investment in the formal sector also bypasses the informal workforce which continues to absorb the bulk of new labour market entrants.

What is more worrying is that the scheme could end up normalising disguised unemployment – where people appear to be employed but are in fact not contributing to output – which is common in sectors such

as agriculture and informal services. The result is low productivity and stagnant or low wages. Enterprises might resort to relabeling existing jobs as 'new employment' to claim the subsidy.

The scheme's special focus on manufacturing also reveals a sectoral blind spot. While manufacturing remains critical to economic transformation, its employment elasticity in India has been steadily declining due to increased automation and capital intensity. Today, manufacturing contributes less than 13% to total employment, while agriculture and services together employ nearly 70% of the workforce. By disproportionately privileging manufacturing through extended incentives, the ELI Scheme may further marginalise large segments of the workforce, particularly women, rural youth, and informal workers, who are more likely to be employed in low-skill services or agriculture. This sectoral imbalance represents an outdated assumption that the manufacturing sector will be the primary engine of job creation.

What could be an alternative?

Although the ELI Scheme is an attempt to address India's unemployment crisis, the policy design indicates that it will deepen structural inequalities in the labour market. It also highlights the absence of mechanisms to address skill development, improve job quality, or social security for the workers in the informal sectors. Investment in skilling and education reforms will instead benefit low-skilled workers. Further, more initiatives should be shifted from short-term employment generation to long-term sustained employment opportunities and enhanced productivity, without compromising on labour rights and bargaining power. Finally, an employment generation drive should avoid dealing with headcounts, and rather focus on being an equitable and sustainable development strategy.

GS. Paper 03 Indian Economy

UPSC Mains Practice Question: भारत के श्रम बाज़ार में नियोजित-केंद्रित प्रोत्साहन योजनाएँ असमानता को गहरा सकती हैं और कौशल असंतुलन को नहीं सुलझातीं। 2025 की एम्प्लॉयमेंट लिंकड इंसेंटिव योजना के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (150 words)

Context :

1 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंकड इंसेंटिव (ELI) योजना को ₹99,446 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य विशेषकर विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, यह योजना नियोजित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती है और भारत के श्रम बाजार की गहरी संरचनात्मक समस्याओं — जैसे कौशल असमानता, औपचारिक-अनौपचारिक क्षेत्र का विभाजन और कम गुणवत्ता वाली नौकरियों — को नजरअंदाज करती है।

ELI योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे**1. नियोजित-केंद्रित दृष्टिकोण**

- वित्तीय प्रोत्साहन सीधे नियोजितों को दिए जाते हैं, श्रमिकों को नहीं।
- यह पूंजी को सब्सिडी देने जैसा है, जिससे पूंजी-श्रम असमानता बढ़ सकती है।
- नियोजितों की सौदेबाजी शक्ति बढ़ेगी → वेतन असमानता और गहरी हो सकती है।

2. कौशल और नौकरी का असंतुलन

- केवल 8.25% स्नातक अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी में हैं।
- अधूरा रोजगार: 53% स्नातक और 36% परास्नातक अर्ध-कुशल या प्रारंभिक कार्यों में।
- वेतन असमानता:
 - केवल 4.2% विशेषज्ञ स्नातक ₹4–8 लाख/वर्ष कमाते हैं।
 - 46% निम्न-कुशल नौकरियों में ₹1 लाख/वर्ष से कम कमाते हैं।
- मात्र 4.9% युवा (15–29 वर्ष) ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया है।
- मजबूत स्किलिंग ढाँचे के बिना, सब्सिडी एक अतैयार कार्यबल को ही रोजगार में धकेल देगी।

3. अनौपचारिक क्षेत्र की उपेक्षा

- भारत की 90% कार्यशक्ति अनौपचारिक है, लेकिन योजना EPFO-पंजीकृत कंपनियों पर केंद्रित है।
- लाभ अपेक्षाकृत सक्षम औपचारिक उद्यमों तक सीमित रहेंगे; अनौपचारिक श्रमिक बाहर रहेंगे।
- इससे श्रम बाजार में संरचनात्मक द्वैतवाद और गहरा सकता है।

4. छुपा हुआ बेरोजगारी (Disguised Unemployment) का खतरा

- कंपनियाँ पुराने पदों को "नए" रोजगार बताकर सब्सिडी ले सकती हैं।
- कृषि और अनौपचारिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कम उत्पादकता और स्थिर/कम वेतन जारी रहेंगे।

5. क्षेत्रीय असंतुलन

- मैन्युफैक्चरिंग पर अत्यधिक जोर, जबकि इसमें रोजगार लोच (Employment Elasticity) लगातार घट रही है।
- मैन्युफैक्चरिंग में <13% कार्यबल; कृषि व सेवाओं में ~70%।
- महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और निम्न-कुशल श्रमिकों के लिए अवसर सीमित।

प्रभाव

- **समानता का हास** – सार्वजनिक धन औपचारिक क्षेत्र को अधिक लाभान्वित करेगा।
- **वित्तीय संसाधनों की बर्बादी** – वास्तविक नए रोजगार नहीं बन सकते।
- **असमानता में वृद्धि** – औपचारिक-अनौपचारिक विभाजन और वेतन असमानता गहरी होगी।
- **श्रम प्रवृत्तियों से असंगति** – सेवाक्षेत्र की बढ़ती भूमिका की अनदेखी।

वैकल्पिक नीति सुझाव

1. **स्किलिंग तंत्र को मजबूत करना**
 - व्यावसायिक प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप और उद्योग-शिक्षा साझेदारी का विस्तार।
 - पाठ्यक्रम में रोजगारोन्मुखी सुधार।
2. **अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण**
 - औपचारिकीकरण (Formalisation) के लिए प्रोत्साहन, दंड नहीं।
 - सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार।
3. **नौकरी की गुणवत्ता पर जोर**
 - स्थायी अनुबंध, श्रमिक अधिकार और उचित वेतन सुनिश्चित करना।
4. **क्षेत्रीय विविधता**
 - कृषि और सेवाओं के साथ-साथ विनिर्माण को समर्थन।
 - श्रम-प्रधान क्षेत्रों (निर्माण, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा) को प्रोत्साहन।
5. **गिनती से अधिक उत्पादकता पर ध्यान**
 - सफलता का आकलन टिकाऊ आजीविका और उत्पादकता वृद्धि से करना, केवल संख्या से नहीं।

निष्कर्ष

ELI योजना बेरोज़गारी की समस्या को हल करने का प्रयास है, लेकिन इसकी मौजूदा संरचना संरचनात्मक असमानताओं को और गहरा सकती है और भारत की रोज़गार समस्या के मूल कारण — कौशल की कमी, अनौपचारिक क्षेत्र की उपेक्षा और क्षेत्रीय असंतुलन — को नहीं सुलझाती। एक टिकाऊ रोज़गार नीति में स्किलिंग, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसर वाले क्षेत्रीय समर्थन को सम्मिलित करना आवश्यक है, ताकि आर्थिक वृद्धि गुणवत्तापूर्ण और समावेशी रोजगार में बदल सके।